चरमराती अर्थव्यवस्था से सिसकती माँ भारती

- अनिल कुमार सिंह

आज भारत में आर्थिक बदहाली से हाहाकार मचा हुआ है या उसके वीभत्स स्वरूप के आने का आगाज है। देशभक्ति जज्बा अवश्य इस समस्या को धारा 370 हटाने की तरफ गर्वान्वित स्वरूप में देख रहा है, लेकिन दैनिक पारिवारिक आवश्यकताएं और उनकी पूर्ति न हो सकने की स्थिति में होने वाला विप्लव सोच कर भी दिल घबरा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू पूँजी संचय पर आधारित है ,जब-जब वैश्विक आघात अर्थव्यवस्था पर पड़ा भारत ने उसका अपनी सचित पूँजी से डटकर मुकाबला किया और भारतीय जनता उस आघात से विचलित नहीं हुई।

भारत एक समय सोने की चिड़िया कहलाता था। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार पहली सदी से लेकर दसवीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था विष्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण व दोहन हुआ। फलस्वरूप 1947 में आज़ादी के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सुनहरी इतिहास का एक खंडहर मात्र रह गई। आज़ादी के बाद से भारत का झुकाव समाजवादी प्रणाली की ओर रहा। सार्वजनिक उद्योगों तथा केंद्रीय आयोजन को बढ़ावा दिया गया। बीसवीं शताब्दी में सोवियत संघ के साथ-साथ भारत में भी इस प्रणाली का अंत हो गया। 1991 में भारत को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद नरसिंह राव की सरकार ने वित्तमंत्री मनमोहन सिंह के निर्देशन में आर्थिक सुधारों की लंबी कवायद शुरु की जिसके बाद धीरे-धीरे भारत विदेशी पूँजी निवेश का आकर्षण बना और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका - भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना। 1991 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता का दौर आरम्भ हुआ। इसके बाद से भारत ने प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की। अप्रत्याशित रूप से वर्ष 2003 में भारत ने 8.4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की। इस दर को दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का एक संकेत समझा गया।

साल 2008 में आई वैष्विक मंदी के दौर में जब दुनिया की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की चूलें हिल गई थीं, तमाम झंझावातों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से अपने पांव डिगाए रही थी। तब देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। तब भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली जो वजहें थीं, अब पीएम मोदी ने मौजूदा दौर में भी ऐसी ही वजहों के सहारे आगे बढ़ने की अपील की है। लालकिले की प्राचीर से अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने मंत्र दिया है - 'लकी कल के लिए लोकल।' देश में राजनीतिक स्थरिता का फायदा मिलने का संकेत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'जब राजनीतिक स्थिरता होती है तो दुनिया का भरोसा बनता है।'

भारत में मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2019 के बजट प्रस्तुतीकरण के बाद चिदंबरम ने कहा कि इस सरकार को विरासत में ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। दुर्भाग्य से पहले दो साल बाद ही सरकार लड़खड़ाने लगी और रफ्तार थमने लगी। इसकी मुख्य वजह नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी का क्रियान्वयन और कर-आतंकवाद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बराबरी और सामाजिक न्याय के साथ उच्च वृद्धि दर की हिमायती है। मोदी सरकार के दौर में ये तीनों बातें प्रभावित हुई हैं।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो स्थिति पिछले कुछ महीनों से देखने में आ रही है, वो देश की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं कही जा सकती है। .ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले चार महीनों के दौरान ना सिर्फ उत्पादन में कमी आई है, बल्कि खरीदार भी कम हुए हैं इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी भी जा रही है। उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) ने दावा किया है कि पिछले तीन महीने में कार और बाइक की बिक्री में गिरावट के चलते एजेंसियों और डीलरों ने ही करीब दो लाख कर्मचारियों की छंटनी की है। पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो ये संख्या कहीं ज्यादा है। ऑटोमोबाइल उद्योग पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें न सिर्फ वाहनों का निर्माण और उनकी बिक्री ही शामिल है बल्कि इस उद्योग में छोटे-बड़े कलपुर्जों को निर्माण से लेकर स्टील इंडस्ट्री तक इसका विस्तार है।

नोटबंदी, जीएसटी एवं देश में सामजिक अस्थिरता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे रसातल की और जाने लगी है, हमने बाजार का सर्वेक्षण किया, लघु-मध्यम उद्योग धंधों के निरीक्षण एवं आंकलन के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में गए वीरान क्लस्टर्स ने हमारा स्वागत किया। अधिकांश मुख्य प्रवेशद्वारों पर ताले मिले। चाय-पान की दुकानें ग्राहकों की भीड़ से मुक्त नजर आयीं। कुछ बड़ी औद्योगि इकाईओं में कार्य चलता मिला, किन्तु वहां भी आधे से अधिक कर्मचारियों की छंटनी हो गयी है। हम थोक बाजार के उस स्थान पर भी पहुंचे जहाँ मालवाहक वाहनों का जमघट रहता है। एक दिन में पांच-छह फेरे लगाने वाले गाड़ी मालिकों ने बताया दो - चार दिन में एक फेरा मिलना भी मुश्किल हो रहा है। इनत तथ्यों से आप बाजार की स्थिति का अंदाजा सहज रूप से लगा सकते हैं।

मेरा भारत फिर भी उल्लसित है, प्रसन्न है - कारण कश्मीर से धारा 370 हटा दी गयी है। ऐसे बहुप्रतीक्षित समर्थकों में मैं भी हूँ - लेकिन उसका यह समय कहीं देश पर भारी न पड़ जाए। भारी-भरकम खर्च सेना पर आने वाला है। अमरीका की व्यापारिक स्थिति भी ठीक नहीं है, वह भी अपने हथियार भारत को बेचने की जुगत में लगा हुआ है। उसके बदले कुछ मुद्दों पर वह भारत का वैष्वित समर्थन करेगा। अपना माल ठिकाने लगा कर भारत से धन वसूलेगा। हमारे बैंक कंगाल हो रहे हैं। निवेशकों ने निवेश रोक लिया है। उनका भरोसा बैंकों पर से भी उठता जा रहा है। बड़े व्यापारी आर्थिक घोटाले कर विदेश भाग गए हैं। उनसे वसूली असंभव दिख रही है। आखिर मौजूदा सरकार कैसे देश को इस संकट से उबारेगी यह देखना है.....जो असंभव प्रतीत हो रहा है। **(प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)**

नोट: मनुज फीचर में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।